

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

Mai Laug I

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 0 149]

मई , बिल्ली, ब्धवार, जुलाई 24, 1968/आवण 2, 1890

No. 149)

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 1968/SRAVANA 2, 1890

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन क कप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1968

संकल्प

विषय.—शिक्षा की राष्ट्रीय नीति

सं० एफ० 30-60/67-प्रार्ष० यू०.--भारतीय समाज में शिक्षा को हमेशा से ही मान्य स्थान दिया जाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता ग्रान्दोलन के महान् नेता शिक्षा के बुनियादी योगदान से परिचित थे ग्रीर राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उसके ग्रसामान्य महत्व पर जोर देते थे। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य मानसिक ग्रीर शारीरिक कार्यों में सामंजस्य पैदा करना था। शिक्षा को लोगों के जीवन के साथ सीघे सम्बद्ध करने के लिए उठाया गया यह एक महान् कदम था। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पहले ग्रन्य ग्रनेक नेताग्रों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा में ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण योग दिया था।

- 2. स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार भौर राज्य सरकारें, राष्ट्रीय प्रगित भौर सुरक्षा के प्रभावी साधन के रूप में शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देती रही हैं। अनेक आयोगों और समितियों ने, जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) भौर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) उल्लेखनीय हैं, शैक्षिक पुर्नानर्माण की समस्याओं की समीक्षा की। इन आयोगों की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए और जैवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में विज्ञान-नीति पर संकल्प पारित होने के बाद विज्ञान, शिल्पविज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास पर विशेष बल दिया जाता रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार पुनरीक्षण किया जाए जिससे शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए नए सिरे से तथा शौर वृद्ध निश्चय के साथ प्रयत्न किया जा सके, और "शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, तथा सभी स्तरों और पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धान्तों और नीतियों" पर सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा आयोग (1964—66) की नियुक्ति की गई। श्रव तक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर काफी चर्चा हुई है और टिप्पणियां की गई हैं। सरकार को इस बात की प्रसन्नता है कि इन चर्चाओं से शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में मतैक्य हो गया है।
- 3. भारत सरकार का यह विश्वास है कि देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा आयोग द्वारा बताई गई स्थूल रूपरेखाओं के आधार पर शिक्षा का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु शिक्षा को लोगों के जीवन के अधिक निकट लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण, शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए लगान्तार प्रयत्न, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणता में सुधार करने के लिए लगातार और ब्यापक प्रयत्न, विज्ञान और शिल्पविज्ञान के विकास पर विशेष बल, तथा नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा और विकास के लिए कृतसंकल्प, चरित्र-सम्पन्न और योग्य युवक और युवितयों का निर्माण हो। तभी शिक्षा राष्ट्रीय विकास कर सकती है, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना पैदा कर सकती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सकती है। विश्व के राष्ट्रों में इस देश को उसकी महान सांस्कृतिक विरासत और उसकी श्रसामान्य सामर्थ्य के अनुरूप योग्य स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है।
- 4. म्रतः भारत सरकार निम्नलिखित सिद्धान्तों के म्राधार पर देश में शिक्षा का विकास करने के लिए संकल्प करती है:——
 - (1) निःशुल्क श्रीर श्रितियायं शिक्षा. चौदह धर्ष तक की वय के सभी बच्चों के लिए निशुल्क श्रीर श्रिनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संविधान के श्रिनुक्छेद 45 के श्रिपीन दिए निवेशक सिद्धान्तों को श्रमल में लाने के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। स्कूलों में चालू व्यर्थता श्रीर ग्रगति को कम करने श्रीर यह सुनि- दिचत करने के लिए कि स्कूल में दाखिल हर छात्र विहित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर ले, उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।
 - (2) प्रध्यापकों का दर्जा, बेतन-भक्ते झीर शिक्षा. (क) शिक्षा की गुणता धीर राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान के लिए उत्तरदायी कारणों में से प्रध्यापक निस्सन्देह सर्वाधिक महस्वपूर्ण हैं । उसके व्यक्तिगत गुणों श्रीर चरित्र, शैक्षिक योग्यताझों एवं व्यवसायिक श्रर्हताझों पर श्रंततः शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयरनों

की सफलता निर्भर है। श्रतः श्रघ्यापकों को समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनकी योग्यताश्रों श्रौर उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुए उनके वेतन-भक्ते तथा श्रन्य सेवा की शर्ते पर्याप्त श्रौर सन्तोषजनक होनी चाहिएं।

- (ख) स्वतंत्र प्रध्ययन तथा प्रनुसंधान सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाशित करने तथा महस्वपूर्ण राष्ट्रीय श्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर भाषण करने श्रौर लिखने की ग्रध्यापकों की रौक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
- (ग) प्रध्यापक शिक्षा, विशेष रूप से ग्रन्तर्सेवा शिक्षा, पर यथोचित बल दिया जाना चाहिए ।
- (3) भ.षाश्चीं का विकास: (क) प्रावेशिक भाषाएं.—भारतीय भाषाश्चीं श्रीर साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास की एक ग्रनिवार्य शर्त है। जब तक यह नहीं किया जाएगा, लोगों की सूजनात्मक शक्तियां क्रियाशील नहीं होंगी, शिक्षा के स्तरों में सुधार नहीं श्राएगा, जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुंचेगा, श्रीर बुद्धिजीवियों तथा जनसाधारण के बीच की खाई यदि चौड़ी न भी हुई तो यथावत् बनी रहेगी। प्राथमिक श्रीर माध्यमिक श्रवस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहूँ त किया जा रहा है। श्रव उनका प्रयोग विश्वविद्यालय ग्रवस्था में भी करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिएं।
- (स) त्रिभाषा सूत्र.—माध्यमिक श्रवस्था में राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र लागू करना ग्रीर जोर-शोर के साथ उसको त्रियान्वित करना चाहिए । इस सूत्र के श्रन्तगंत एक श्राषुनिक भारतीय भाषा तरजीहन्, एक दक्षिण भारतीय भाषा, का श्रध्ययन तथा साथ ही हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी ग्रीर श्रंग्रेजी श्रीर श्रहिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा तथा श्रंग्रेजी के साथ हिन्दी का श्रध्ययन शामिल है। विद्वविद्यालयों श्रीर कालेजों में हिन्दी तथा/या ग्रंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रमों की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि छात्र विहित विद्वविद्यालय मानकों के अनुरूप इन भाषाश्रों में प्रवीणता प्राप्त कर सकें।
- (ग) हिन्दी.—हिन्दी के विकास ग्रौर प्रसार का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करते समय इस बात का समृचित घ्यान रखना चाहिए कि यह भाषा संविधान के श्रनुच्छेद 351 के उपबन्धों के श्रनुसार भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के लिए श्रभिष्यक्ति का माध्यम बन सकेगी। श्रहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा की श्रन्य संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- (घ) **संस्कृत.**—भारतीय भाषात्रों के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व को देखते हुए ग्रौर देश की सांस्कृतिक एकता के लिए उसके ग्रपूर्व योगदान की दृष्टि से स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के ग्रथ्यापन की सुविधाएं ग्रधिक

विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिएं। इस भाषा के प्रध्यापन के नए तरीकों के विकास की प्रोत्साहन देना चाहिए श्रीर प्रथम श्रीर द्वितीय डिग्री श्रवस्थाश्रों पर, उन पाठ्यक्रमों में जहां कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है (जैसे, श्राधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत विद्या तथा भारतीय दर्शन) संस्कृत के श्रध्यापन की सम्भावनाश्रों की खोज की जानी चाहिए।

- (ङ) ग्रन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं. अंग्रेजी तथा श्रन्य श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषाश्रों के श्रध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । संसार में ज्ञान का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है, विशेषकर विज्ञान श्रीर शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में । भारत को न केबल इस विकास को बनाए रखना है बल्कि श्रपनी श्रोर से भी उसमें सार्थक योग-दान करना है । इस उद्देश्य से श्रंग्रेजी के श्रध्ययन को विशेष रूप से पुष्ट करना माहिए ।
- (4) शिक्षा के श्रवसरों का सम:नीकरण.—शिक्षा की समस्यात्रों के समानीकरण के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किए जाने चाहिएं।
 - (क) शिक्षा की सुविधाय्रों की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक श्रसंतुलन को मिटाना चाहिए तथा ग्रामीण ग्रौर श्रन्य पिछड़े इलाकों में शिक्षा की श्रच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिएं।
 - (ख) सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा श्रायोग की सिफ़ारिशों में बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। पब्लिक स्कूलों के समान विशेष स्कलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के श्राधार पर किया जाना चाहिए और सामाजिक धर्मों के पृथक्- करण को बचाने के लिए फीस-माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे संविधान के अनुच्छोद 30 के अन्तर्गत श्रस्पसंख्यकों के श्रिधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - (ग) न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपान्तरण की गति को तीव्र करने के लिए भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।
 - (घ) पिछड़े बर्गों तथा विशेष रूप से ब्रादिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए श्रीधक तीब्र प्रयत्नों की श्रावश्यकता है।
 - (ङ) विकलांगों भ्रौर भानसिक रूप से श्रशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाम्रों का विकास करना चाहिए श्रौर ऐसे समन्वित कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ये बच्चे नियमित स्कूलों में ग्रध्ययन प्राप्त कर सकें।

- (5) प्रतिभा की पहचान.—प्रवीणता का विकास करने के लिए यह श्रावश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी से छोटी उम्प्र में खोज निकालना चाहिए श्रोर उनके विकास के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन श्रीर श्रवसर प्रदान किए जाने चाहिएं।
- (6) फ़ार्यानुभव श्रीर राष्ट्रीय सेवा.—परस्पर सेवा श्रीर सहायता के उपयुक्त कार्य-कमों द्वारा स्कूलों श्रीर समुदायों की एँक दूसरों के निकट लाना चाहिए। तदनुसार कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा, जिसमें सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक तथा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं, शिक्षा का श्रमिन्न श्रंग होने चाहिए । इन कार्यक्रमों में स्वावलम्बन, चरित्र-निर्माण तथा सामाजिक उद्देश्यों के लिए श्रात्मोत्सर्ग की भावना का विकास श्रादि पर बल दिया जाना चाहिए।
- (7) विज्ञान जिक्का तथा ग्रमुसंधान.—राष्ट्रीय ग्रर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के शिए विज्ञान शिक्षा तथा ग्रमुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल ग्रवस्था के ग्रन्त तक विज्ञान ग्रीर गणित सामान्य शिक्षा का ग्रमिश ग्रंग होने चाहिए।
- (8) **कृषि तथा उद्योग की शिक्षा.**—कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।
 - (क) प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए । जहां तक हो सके ये सिश्वविद्यालय एक अहाने में स्थित स्वतःपूर्ण होने चाहिए; पर जहां आवश्यक हो इनके विभिन्न श्रहातों में स्थित संघटक कालेज भी हो सकते हैं । अन्य विश्वविद्यालयों में भी जहां आवश्यक संभाव-नाएं हैं कृषि के एक या उससे अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए पुख्ता विभाग खोले जाने चाहिएं ।
 - (ख) तकनीकी शिक्षा में, उनके एक ग्रभिन्न ग्रांग के रूप में, उद्योगों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा तथा ग्रनुसंधान का सम्बन्ध उद्योग से बहुत निकट का होना चाहिए ताकि एक से दूसरे में कार्मिक ग्रा जा सकें, ग्रीर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सुविधान्नों की व्यवस्था, रूपरेखा तैयार करने तथा श्रावधिक समीक्षा के लिए व्यवस्था हो सके।
 - (ग) देश की श्रौद्योगिक, कृषि तथा श्रन्य तकनीकी जनशक्ति की ग्रावश्यकताश्रों की निरन्तर समीक्षा होती रहनी चाहिए तथा शिक्षा संस्थाश्रों से निकले छात्रों तथा रोजगार के भ्रवसरों के बीच उचित संसुलन बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

(9) पुरतकों का उत्पादन.—प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को ग्राकषित करके पुस्तकों की गुणता में सुधार किया जाना चाहिए। स्कूलों भ्रौर विश्वविद्यालयों के लिए उच्च-स्तर की पाठ्चपुस्तकों प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। बार-बार पाठ्चपुस्तकों बदलने से बचना चाहिए ग्रौर इन पुस्तकों का मूल्य इतना होना चाहिए कि मामूली हैसियत का छात्र भी उन्हें लरीद सके।

व्यावसायिक पैमाने पर स्वायत्त पुस्तक निगमों की स्थापना की सम्भावनाश्रों की परीक्षा की जानी चाहिए श्रौर कुछ ऐसी बुनियादी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए जो देश भर के लिए समान हों। बच्चों की पुस्तकों श्रौर प्रादेशिक भाषाश्रों की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- (10) परीक्षाएं. —परीक्षा सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षाश्रों की विश्वसनीयता ग्रौर जनकी मान्यता में सुधार हो सके ग्रौर मूल्यांकन एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि के स्तर को उन्नत करने मे सहायता देना, होना चाहिए न कि समय-विशेष में उसके कार्य की गुणता को देख कर उसे 'प्रमाणपत्र' दे देना ।
- (11) माध्यमिक शिक्षा: (क) माध्यमिक (तथा उच्चतर) स्तर पर शिक्षा के श्रवसर सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण का एक प्रमुख उपकरण है। श्रतएव माध्य-मिक शिक्षा की सुविधाएं तेजी से उन क्षेत्रों श्रौर वर्गों को भी दी जानी चाहिएं जिनको श्राज तक यह प्राप्त नहीं हो सकीं।
 - (ख) इस भ्रवस्था पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने की भ्रावश्यकता है। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था मोटे तीर पर विकासमान भ्रयंव्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार भ्रवसरों के भ्रनु- रूप होनी चाहिए। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावी रूप से समापक बनाने के लिए यह सम्बन्ध भ्रावश्यक है। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से विशाखन किया जाना चाहिए ताकि उसके भ्रन्तर्गत भ्रनेक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा बाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध, कला भ्रीर शिल्प, भ्रनुसचिवीय प्रशिक्षण, भ्रादि भ्रा सकें।
- (12) विद्यविद्यालय शिक्षा : (क) एक कालेज या विद्यविद्यालय में कितने पूर्ण-कालिक छात्र भर्ती किए जाएं इस की संख्या प्रयोगशालाश्रों, पुस्तकालयों सथा श्रन्य सुविधाश्रों श्रौर कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए ।

- (ख) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी की श्रावश्यकता है। उनकी स्थापना तभी की जानी चाहिए जब पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध हो तथा उपयुक्त मानकों के बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई हो।
- (ग) इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर विशेष व्यान दिया जाना चाहिए ग्रीर साथ ही प्रशिक्षण श्रीर श्रनुसंधान के मानकों में सुधार करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (घ) उच्च शिक्षा के केन्द्रों की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए श्रौर कुछ थोड़े से ऐसे 'केन्द्र स्कूल' स्थापित किए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य श्रनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण में उच्चतम मानक स्थापित करना हो ।
- (ङ) विश्वविद्यालयों में ग्रनुसंधान को सामान्यतया ग्रधिक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक हो सके ग्रनुसंधान की संस्थाएं विश्वविद्यालय के ग्रन्तर्गत ही कार्य करें ग्रथवा उनके साथ निकट सम्पर्क रखें।
- (13) ग्रल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमः.— ग्रल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम विद्वविद्यालय स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने चाहिएं। यही सुविधाएं माध्यमिक स्कूल के छात्रों, ग्रध्यापकों तथा श्रीधोगिक, कृषि सम्बन्धी तथा ग्रन्य प्रकार के कर्मचारियों के लिए भी दी जानी चाहिएं। ग्रल्पकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को वही दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि पूर्णकालिक शिक्षा को। इस प्रकार की सुविधाश्रों से स्कूल से रोज-गार की ग्रोर जाने में ग्राराम रहेगा, शिक्षा के हित को बढ़ावा मिलेगा तथा उन बहुत से लोगों को ग्रवसर भी मिल सकेगा जो ग्रागे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर पूर्णकालिक ग्राधार पर नहीं कर सकते।
- (14) स अ ता तथा प्रोह शिक्षा ा अवार.—(क) लोक निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल लोकतंत्रीय संस्थाओं के कार्य में भाग लने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा कार्यक्रमों को गति तीव्र करने के लिए (विशेषकर कृषि के क्षेत्र में) ही नहीं बल्कि सामान्य राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए भी आवश्यक है। बड़ी वाणिज्यिक, श्रीद्योगिक तथा अन्य संस्थापनाओं के कर्मचारियों को जितनी जल्दी हो सके कामचलाऊ रूप से साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य में मार्गदर्शन सरकारी क्षेत्र के श्रीद्योगिक उपक्रमों को करना चाहिए, अध्यापकों और छात्रों को सिक्रय रूप से साक्षरता श्रभियानों का संगठन करना चाहिए, विशेष रूप से सामाजिक तथा। राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के रूप में।
 - (ख) युवा कृषकों की शिक्षा तथा स्वनियोजन के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने पर विशेष बल देना चाहिए ।

- (15) खेलकूद.—खेलकूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए श्रीर इसका उद्देश श्रीसत विद्यार्थी तथा इस क्षेत्र में प्रवीणता दिखाने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी शारीरिक योग्यता श्रीर खेलकारी को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए। जहां पर खेल के मैदानों तथा श्रीखल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास की श्रन्य सुविधाएं नहीं हैं, वहां ये सुविधाएं प्राथमिकता के श्राधार पर दी जानी चाहिएं।
- (16) ग्रारंपसंख्यकों की शिक्षा.—न केवल श्रल्पसंख्यकों के श्रिधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक श्रिभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में श्रगस्त, 1961 में एक वक्तव्य जारी किया गया था।
- (17) शिक्षा का ढांचा.—यह भ्रावश्यक है कि देश के हर भाग में शिक्षा का ढांचा मोटे तौर पर एक समान हो । इसका उद्देश्य भ्रन्ततः 10 → 2 → 3 पैटर्न को भ्रपनाना होना चाहिए, इसमें स्थानीय परिस्थितियों के भ्रनुसार दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक श्रवस्था या तो स्कूलों में हो या कालेजों में या दोनों में हो ।
- 5. ऊपर बताई गई रूपरेखा के श्रनुसार शिक्षा का पुनर्गठन करने में श्रितिरिक्त धन की श्रावश्यकता होगी। उहेंश्य यह होमा चाहिए कि धीरेधीरे शिक्षानिवेश को बढ़ाया जाए ताकि जितनी जल्दी हो सके वह राष्ट्रीय श्राय के 6 प्रतिशत खर्च के स्तर पर पहुंच जाए।
- 6. भारत सरकार इस बात को मानती है कि शिक्षा का पुनर्निर्माण सरल काम नहीं है। न केवल साधनों की कमी है, वरन् समस्याएं अत्यधिक जटिल है। यह देखते हुए कि शिक्षा विज्ञान तथा अनुसंधान भौतिक तथा जनसाधनों के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का बीड़ा उठाने के श्रतिरिक्त राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के उन कार्य-कमों के कार्यन्वयन में सहायता देगी जहां राज्यों श्रीर केन्द्र के समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है।
- 7. भारत सरकार हर पांच वर्ष में प्रगति की समीक्षा करेगी श्रौर द्यागे के विकास के लिए मार्गदर्शक सुक्षाव देगी ।

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए ।

यह भी श्रादेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

> जी० के० चन्दीरमानी, सचिव, भारत सरकार ।

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 24th July, 1968

RESOLUTION

Subject:—National Policy on Education

- No. F. 30-60/67-IU.—Education has always been accorded an honoured place in Indian society. The great leaders of the Indian freedom movement realised the fundamental role of education and throughout the nation's struggle for independence, stressed its unique significance for national development. Gandhiji formulated the scheme of basic education seeking to harmonize intellectual and manual work. This was a great step forward in making education directly relevant to the life of the people. Many other national leaders likewise made important contributions to national education before independence.
- 2. In the post-independence period, a major concern of the Government of India and of the States has been to give increasing attention to education as a factor vital to national progress and security. Problems of educational reconstruction were reviewed by several Commissions and Committees, notably the University Education Commission (1948-49) and the Secondary Education Commission (1952-53). Some steps to implement the recommendations of these commissions were taken; and with the passing of the Resolution on Scientific Policy under the leadership of Jawaharlal Nehru, the development of science, technology and scientific research received special emphasis. Towards the end of the Third Five Year Plan, a need was felt to hold a comprehensive review of the educational system with a view to initiating a fresh and more determined effort at educational reconstruction; and the Education Commis-(1964-66) was appointed to advise Government on "the national pattern of education and on the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects." The Report of the Education Commission has since been widely discussed and commented upon. Government is happy to note that a general consensus on the national policy on education has emerged in the course of these discussions.
- 3. The Government of India is convinced that a radical reconstruction of education on the broad lines recommended by the Education Commission is essential for economic and cultural development of the country, for national integration and for realising the ideal of a socialist pattern of society. This will involve a transformation of the system to relate it more closely to the life of the people; a sustained and intensive effort to raise the quality of education at all stages; an emphasis on the development of science and technology; and the cultivation of moral and social values. The educational system must produce young men and women of character and ability committed to national service and development. Only then will education be able to play its vital role in promoting national progress, creating a sense of common citizenship and culture, and strengthening national integration. This is necessary if the country is to attain its rightful place in the comity of nations in conformity with its great cultural heritage and its unique potentialities.

- 4. The Government of India accordingly resolves to promote the development of education in the country in accordance with the following principles:—
- (1) Free and Compulsory Education.—Strenuous efforts should be made for the early fulfilment of the Directive Principle under Article 45 of the Constitution seeking to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14. Suitable programmes should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation in schools and to ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course.
- (2) Status, Emoluments and Education of Teachers.—(a) Of all the factors which determine the quality of education and its contribution to national development, the teacher is undoubtedly the most important. It is on his personal qualities and character, his educational qualifications and professional competence that the success of all educational endeavour must ultimately depend. Teachers must therefore be accorded an honoured place in society. Their emoluments and other service conditions should be adequate and satisfactory having regard to their qualifications and responsibilities.
- (b) The academic freedom of teachers to pursue and publish independent studies and researches and to speak and write about significant national and international issues should be protected.
- (c) Teacher education, particularly in-service education, should receive due emphasis.
- (3) Development of Languages: (a) Regional Languages.—The energetic development of Indian languages and literature is a sine qua non for educational and cultural development. Unless this is done, the creative energies of the people will not be released, standards of education will not improve, knowledge will not spread to the people, and the gulf between the intelligentsia and the masses will remain, if not widen further. The regional languages are already in use as media of education at the primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage.
- (b) Three-Language Formula.—At the secondary stage, the State Governments should adopt, and vigorously implement, the three-language formula which includes the study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking States, and of Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking States. Suitable courses in Hindi and/or English should also be available in universities and colleges—with a view to improving the proficiency of students in these languages up to the prescribed university standards.
- (c) Hindi.—Every effort should be made to promote the development of Hindi. In developing Hindi as the link language, due care should be taken to ensure that it will serve, as provided for in Article 351 of the Constitution, as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. The establishment, in non-Hindi States, of colleges and other institutions of higher education which use Hindi as the medium of education should be encouraged.

- (d) Sanskrit.—Considering the special importance of Sanskrit to the growth and development of Indian languages and its unique contribution to the cultural unity of the country, facilities for its teaching at the school and university stages should be offered on a more liberal scale. Development of new methods of teaching the language should be encouraged, and the possibility explored of including the study of Sanskrit in those courses (such as modern Indian languages, ancient Indian history, Indology and Indian philosophy) at the first and second degree stages, where such knowledge is useful.
- (e) International Languages.—Special emphasis needs to be laid on the study of English and other international languages. World knowledge is growing at a tremendous pace, especially in science and technology. India must not only keep up with this growth but should also make her own significant contribution to it. For this purpose, the study of English deserves to be specially strengthened.
- (4) Equalisation of Educational Opportunity.—Strenuous efforts should be made to equalise educational opportunity.
- (a) Regional imbalances in the provision of educational facilities should be corrected and good educational facilities should be provided in rural and other backward areas.
- (b) To promote social cohesion and national integration, the Common School System as recommended by the Education Commission should be adopted. Efforts should be made to improve the standard of education in general schools. All special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free-studentships to prevent segregation of social classes. This will not, however, affect the rights of minorities under Article 30 of the Constitution.
- (c) The education of girls should receive emphasis, not only on grounds of social justice, but also because it accelerates social transformation.
- (d) More intensive efforts are needed to develop education among the backward classes and especially among the tribal people.
- (e) Educational facilities for the physically and mentally handicapped children should be expanded and attempts should be made to develop integrated programmes enabling the handicapped children to study in regular schools.
- (5) Identification of Talent.—For the cultivation of excellence, it is necessary that talent in diverse fields should be identified at as early an age as possible, and every stimulus and opportunity given for its full development.
- (6) Work-Experience and National Service.—The school and the community should be brought closer through suitable programmes of mutual service and support. Work-experience and national service including participation in meaningful and challenging programmes of community service and national reconstruction should accordingly become an integral part of education. Emphasis in these programmes should be on self-help, character formation and on developing a sense of social commitment.

- (7) Science Education and Research.—With a view to accelerating the growth of the national economy, science education and research should receive high priority. Science and mathematics should be an integral part of general education till the end of the school stage.
- (8) Education for Agriculture and Industry.—Special emphasis should be placed on the development of education for agriculture and industry.
- (a) There should be at least one agricultural university in every State. There should, as far as possible, be single campus universities; but where necessary, they may have constituent colleges on different campuses. Other universities may also be assisted, where the necessary potential exists, to develop strong departments for the study of one or more aspects of agriculture.
- (b) In technical education, practical training in industry should form an integral part of such education. Technical education and research should be related closely to industry, encouraging the flow of personnel both ways and providing for continuous co-operation in the provision, design and periodical review of training programmes and facilities.
- (c) There should be a continuous review of the agricultural, industrial and other technical manpower needs of the country and efforts should be made continuously to maintain a proper balance between the output of the educational institutions and employment opportunities.
- (9) Production of Books.—The quality of books should be improved by attracting the best writing talent through a liberal policy of incentives and remuneration. Immediate steps should be taken for the production of high quality text-books for schools and universities. Frequent changes of text-books should be avoided and their prices should be low enough for students of ordinary means to buy them. The possibility of establishing autonomous book corporations on commercial lines should be examined and efforts should be made to have a few basic text-books common throughout the country. Special attention should be given to books for children and to university level books in regional languages.
- (10) Examinations.—A major goal of examination reforms should be to improve the reliability and validity of examinations and to make evaluation a continuous process aimed at helping the student to improve his level of achievement rather than at 'certifying' the quality of his performance at a given moment of time.
- (11) Secondary Education.—(a) Educational opportunity at the secondary (and higher) level is a major instrument of social change and transformation. Facilities for secondary education should accordingly be extended expeditiously to areas and classes which have been denied these in the past.
- (b) There is need to increase facilities for technical and vocational education at this stage. Provision of facilities for secondary and vocational education should conform broadly to requirements of the developing economy and real employment opportunities. Such linkage is necessary to make technical and vocational education at the secondary stage effectively terminal. Facilities for technical and vocational education should be suitably diversified to cover a large number of fields such as agriculture, industry, trade and commerce, medicine and public health, home management, arts and crafts, secretarial training, etc.

- (12) University Education.—(a) The number of whole-time students to be admitted to a college or university department should be determined with reference to the laboratory, library and other facilities and to the strength of the staff.
- (b) Considerable care is needed in establishing new universities. They should be started only after an adequate provision of funds has been made for the purpose and due care has been taken to ensure proper standards.
- (c) Special attention should be given to the organization of post-graduate courses and to the improvement of standards of training and research at this level.
- (d) Centres of advanced study should be strengthened and a small number of 'clusters of centres' aiming at the highest possible standard in research and training should be established.
- (e) There is need to give increased support to research in universities generally. The institutions for research should, as far as possible, function within the fold of universities or in intimate association with them.
- (13) Part-time Education and Correspondence Courses.—Part-time education and correspondence courses should be developed on a large scale at the university stage. Such facilities should also be developed for secondary school students, for teachers and for agricultural, industrial and other workers. Education through part-time and correspondence courses should be given the same status as full-time education. Such facilities will smoothen transition from school to work, promote the cause of education and provide opportunities to the large number of people who have the desire to educate themselves further but cannot do so on a full-time basis.
- (14) Spread of Literacy and Adult Education.—(a) The liquidation of mass illiteracy is necessary not only for promoting participation in the working of democratic institutions and for accelerating programmes of production, especially in agriculture, but for quickening the tempo of national development in general. Employees in large commercial, industrial and others concerns should be made functionally literate as early as possible. A lead in this direction should come from the industrial undertakings in the public sector. Teachers and students should be actively involved in organising literacy campaigns, especially as part of the Social and National Service Programme.
- (b) Special emphasis should be given to the education of young practising farmers and to the training of youth for self-employment.
- (15) Games and Sports.—Games and sports should be developed on a large scale with the object of improving the physical fitness and sportsmanship of the average student as well as of those who excel in this department. Where playing fields and other facilities for developing a nation-wide programme of physical education do not exist, these should be provided on a priority basis.
- (16) Education of Minorities.—Every effort should be made not only to protect the rights of minorities but to promote their educational interests as suggested in the statement issued by the Conference of the Chief Ministers of States and Central Ministers held in August 1961.

- (17) The Educational Structure.—It will be advantageous to have a broadly uniform educational structure in all parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges or both according to local conditions.
- 5. The reconstruction of education on the lines indicated above will need additional outlay. The aim should be gradually to increase the investment in education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.
- 6. The Government of India recognizes that reconstruction of education is no easy task. Not only are the resources scarce but the problems are exceedingly complex. Considering the key role which education, science and research play in developing the material and human resources of the country, the Government of India will, in addition to undertaking programmes in the Central sector, assist the State Governments for the development of programmes of national importance where coordinated action on the part of the States and the Centre is called for.
- 7. The Government of India will also review, every five years, the progress made and recommend guidelines for future development.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for Information.

G. K. CHANDIRAMANI, Secretary to the Government of India.